 राजस्थान पत्रिका 22.07.2016

डीजल का विकल्प

जल्द बायो फ्यूल से सरपट दौड़ेंगे वाहन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

उदयपुर. डीजल के बढ़ते दामों से चिंतित आम आदमी के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने रतनजोत से बायो फ्यूल का जो विकल्प निकाला, वह सच होने जा रहा है। आगामी 2-3 वर्षों के बाद बायो फ्यूल पम्प पर बिकता हुआ दिखाई देगा। बायो फ्यूल से संचालित वाहन पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त होंगे और गाड़ी तेजी गति से दौड़ेगी।

बायो फ्यूल की बिक्री के लिए दो माह पहले सरकार ने नीति बनाई। डीजल व पेट्रोल बिक्री के लिए एजेंसी लेना पड़ती है लेकिन बायो फ्यूल के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी। कोई भी इसकी बिक्री कर सकेगा। वर्तमान में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (आरएसएमएम) के डम्पर व कई सरकारी गाड़ियां इससे चलाई जा रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग के विशेषाधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि रतनजोत के एक पौधे की कीमत 3 से 5 रुपए आती है। इसके बाद किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आता है। प्रोसेसिंग यूनिट, बीज निकालना आदि खर्चों के बाद इसकी एक लीटर की कीमत लगभग 46 रुपए आ रही है, जबकि डीजल की 56 रुपए। इसमें एक पौधा तीन साल के बाद फल देना शुरू कर देता है। एक पौधे से लगभग 2-4 किलोग्राम बीज मिलते है। एक हैक्टेयर में 2500 पौधे लगाए जाते हैं जिनसे पांच हजार किलो ग्राम बीज मिलते है। इनकी खरीद दर 12 रुपए प्रति किलो ग्राम निर्धारित की गई है।

12 जिलों में हो रहा उत्पादन

रतनजोत का उत्पादन उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चितौड़गढ़, भीलवाड़ा, बारां, कोटा, बूंदी, सिरोही, झालावाड़ में किया जा रहा है। सरकार फिलहाल सिर्फ बंजर भूमि काम में ले रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी शुरुआत कृषि भूमि पर नहीं की गई है। हालांकि कोई अपने स्तर पर इसकी खेती करे तो इससे अधिक फायदा मिल सकता है। इससे फायदे को देख सभी इसी तरफ रुख कर लेंगे तो खाद्यान्न संकट हो सकता है, इसलिए सरकार सिर्फ बंजर भूमि का उपयोग कर रही है। केन्द्र व राज्य सरकार ने रतनजोत उत्पादन से बायो फ्यूल का उपयोग कर 2022 तक देश में डीजल आयात को 10 प्रतिशत तक कम करने की योजना बनाई है। अब तक 88 हजार लीटर का उत्पादन हो चुका है। रतनजोत बीज के संग्रहण में हो रही समस्या को राजस संघ व राज फेड दूर करेंगे।

खाड़ी तेल का तोड़ झाड़ी तेल

कारगर नीति जरूरी : गोयल

बायो फ्यूल की राष्ट्रीय कार्यशाला में आए मंत्री

उदयपुर. राज्य सरकार तथा केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साझे में गुरुवार को स्केलिंग-अप एंड मैन स्ट्रीमिंग ऑफ बायो फ्यूल इन इंडिया विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला हुई। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने राज्य में जैव ईंधन के उत्पादन की संभावनाओं को मूर्त रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को बायो डीजल पॉलिसी राज्यों की बेहतरी के लिए प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है। राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले प्रदेश में रतनजोत उत्पादन बेहतर बायो फ्यूल का आधार बन सकता है। इसके लिए सरकार विशेष इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए जमीन देने को तैयार है। इसके लिए केन्द्र को तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन देने पर विचार करना चाहिए। विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुदर्शन सेठी, बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ एसएस राठौड़, राजसमंद कलक्टर अर्चना सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। तिलहन उत्पादन एवं करंज पौधरोपण के लिए तकनीक आदि पुस्तकों का विमोचन एवं लेखक डॉ. पीसी चपलोत का सम्मान भी हुआ। बायो फ्यूल सेल अध्यक्ष अन्ना पाटील ने कहा कि बायो फ्यूल उत्पादन से डीजल-पेट्रोल के विकल्प सृजित होंगे, बेरोजगारी भी कम होगी। मंत्रालय की संयुक्त सचिव वर्षा जोशी ने कहा कि अग्रणी राज्यों एवं दक्ष तकनीकी विशेषज्ञों एवं तकनीशियनों के अनुभव साझा कर बायो फ्यूल पॉलिसी नोट तैयार करवा रहे हैं। राज्यों में जांच प्रयोगशाला प्लांट एवं जिला स्तर विस्तार केन्द्र खोलने की भी योजना है। इसमें केन्द्र 40 फीसदी मदद करेगा।